

■ राज्यों का सहयोग:

- चूँकि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है और राज्यों द्वारा इस योजना के वित्तपोषण में 40% का योगदान दिया जाएगा, इसलिये मौजूदा 'राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं' का 'आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के साथ समन्वय स्थापित करना महत्त्वपूर्ण होगा।
 - पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने इस योजना को लागू नहीं किया है।

■ लागत का बोझ:

- देखभाल प्रदाताओं और केंद्र के बीच लागत एक विवादित मुद्दा है तथा कई अस्पताल सरकार के प्रस्तावों को अव्यावहारिक मानते हैं।

■ अपर्याप्त स्वास्थ्य क्षमताएँ:

- सार्वजनिक क्षेत्र की खराब स्वास्थ्य क्षमताओं में सुधार के लिये नजीक क्षेत्र के प्रदाताओं के साथ आवश्यक भागीदारी और गठबंधन की आवश्यकता है।
- ऐसी परिस्थितियों में सेवाओं का प्रावधान तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब प्रदाताओं को उनकी सेवाओं के लिये जवाबदेह ठहराया जाए।

■ अनावश्यक उपचार:

- 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017' में माध्यमिक और तृतीयक अस्पतालों से शुल्क के बदले स्वास्थ्य सेवाओं की "रगनीतिक खरीद" का प्रस्ताव शामिल है।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अनुबंध जो कवित्तीय मुआवजा पैकेज प्राप्त करेंगे, उन्हें स्पष्ट रूप से अधिसूचित दिशा-निर्देशों और मानक उपचार प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा ताकि अनावश्यक उपचार की संभावना को लेकर जाँच की जा सके।

योजना की उपलब्धियाँ:

■ गरीबों के लिये फायदेमंद:

- कार्यान्वयन के पहले 200 दिनों में PMJAY ने 20.8 लाख से अधिक गरीब और वंचित लोगों को लाभान्वित किया है, जिनमें 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क इलाज मिला चुका है।

■ कोविड-19 के दौरान:

- शुरुआत से ही PMJAY की एक प्रमुख विशेषता इसकी पोर्टेबिलिटी है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि प्रवासी श्रमिक देश में कहीं भी सूचीबद्ध अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं, भले ही उनके निवास की स्थिति कुछ भी हो।

आगे की राह

- भारत के अपने [सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज \(UHC\)](#) के लक्ष्यों को पूरा करने में ABPMJAY कार्यक्रम बड़े स्तर पर महत्वाकांक्षी प्रणालीगत सुधार का अवसर प्रस्तुत करता है।
 - इसके लिये लंबे समय से कम वित्तपोषित स्वास्थ्य प्रणाली में संसाधनों को शामिल करने की आवश्यकता होगी, यद्यपि यह योजना भारत को UHC की ओर नरंतर गति प्रदान करने के लिये है, अतः इसके साथ शासन, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंधन के परस्पर संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
 - भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक व्यय वैश्विक स्तर पर सबसे कम है।
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के उचित उपयोग से स्वास्थ्य सेवा की समग्र लागत को और कम किया जा सकता है। एआई-पावरड मोबाइल एप्लीकेशन (AI-Powered Mobile Applications) उच्च गुणवत्तापूर्ण, कम लागत, स्मार्ट वेबनेस समाधान प्रदान कर सकते हैं। आयुष्मान भारत हेतु स्केलेबल (Scalable) और इंटर-ऑपरेबल (Inter-Operable) आईटी प्लेटफॉर्म इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स